vinetur

डेल्टा ने 7.42 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कर विवाद को जिम्बाब्वे के Fiscal Court में उठाया

यह मामला तय कर सकता है कि मुद्रा में बदलाव के दौरान किए गए पुराने कर भुगतानों का श्रेय जिम्बाब्वे किस तरह देगा

रविवार, 15 नवंबर 2026



डेल्टा कॉरपोरेशन का जिम्बाब्वे रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ कर विवाद Fiscal Court पहुंच गया है। इससे यह मामला और गंभीर हो गया है, जो तय कर सकता है कि मुद्रा में भारी उतार-चढ़ाव वाले वर्षों के दौरान किए गए पुराने कर भुगतानों को जिम्बाब्वे किस तरह देखता है।

30 सितंबर 2026 को समाप्त छह महीनों के नतीजों में डेल्टा ने कहा कि 2019 से 2021 की अवधि से जुड़े मूल्य वर्धित कर और आयकर आकलनों की गणना को लेकर मतभेद अब भी बने हुए हैं। कंपनी के अनुसार, अदालतें आकलनों की वैधता की पुष्टि कर चुकी हैं, लेकिन कर प्राधिकरण ने रकम की गणना कैसे की, भुगतानों का आवंटन कैसे किया और भुगतान किस मुद्रा में हुआ, इस आधार पर उसका हिसाब कैसे रखा—इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है।

ये मुद्दे अब Special Court for Income Tax Appeals के समक्ष हैं, जिसे आम तौर पर Fiscal Court कहा जाता है। डेल्टा

ने यह भी कहा कि 2024 के उसके VAT आकलनों को लेकर High Court में दायर एक अलग याचिका पर अब भी सुनवाई बाकी है।

डेल्टा के नवंबर के तिमाही वक्तव्य के अनुसार, 30 सितंबर तक कुल आकलन करीब US $97 million थे। कंपनी ने कहा कि जिम्बाब्वे की "पहले भुगतान करो, बाद में बहस" व्यवस्था के तहत वह पहले ही US $22.8 million चुका चुकी है। इसके बाद करीब US $74.2 million की रकम पर अपील लंबित है।

विवाद के केंद्र में डेल्टा का यह तर्क है कि मूल कर देनदारियां बनने के समय स्थानीय मुद्रा में किए गए उसके भुगतान वैध थे और किसी भी बकाया राशि की गणना में उन्हें पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। कंपनी के मुताबिक, असहमति सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितना कर देय है। मामला उस कानूनी तरीके का भी है जिसके तहत अलग-अलग मौद्रिक अवधियों में कर देनदारियों की दोबारा गणना की जाती है—इसमें यह भी शामिल है कि एक मुद्रा में किए गए भुगतानों को दूसरी मुद्रा में व्यक्त आकलनों के विरुद्ध कैसे समायोजित किया जाए।

यह मामला जिम्बाब्वे की मुद्रा नीति में बार-बार हुए बदलावों से पैदा हुए दबाव को दिखाता है। इन बदलावों के चलते कंपनियों, नियामकों और अदालतों को ऐसे करों से निपटना पड़ा है जो एक मौद्रिक व्यवस्था के तहत लगे और दूसरी व्यवस्था में दोबारा आंके गए। महंगाई, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और वैध मुद्रा के नियमों में बदलाव के दौर में काम करने वाले कारोबारों के लिए पुराने भुगतानों का हिसाब मौजूदा देनदारियों पर बड़ा असर डाल सकता है।

जिम्बाब्वे का कानून आम तौर पर राजस्व प्राधिकरण को आकलित कर वसूलते रहने की अनुमति देता है, भले ही करदाता उस दावे को चुनौती दे रहा हो। Value Added Tax Act कहता है कि अपील करने से भुगतान की बाध्यता अपने-आप नहीं रुकती। Fiscal Appeal Court Act में भी इसी तरह का प्रावधान है। यह व्यवस्था "पहले भुगतान करो, बाद में बहस" के सिद्धांत को समर्थन देती है, जिसके तहत संबंधित प्राधिकरण के अन्यथा निर्णय लेने तक करदाता को पहले भुगतान करना होता है।

डेल्टा ने कहा कि आकलनों को चुनौती देते हुए भी उसने इस व्यवस्था के तहत भुगतान जारी रखा है और ZIMRA के साथ भुगतान संबंधी व्यवस्थाएं की हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि विवादित देनदारी का जो भी हिस्सा अंततः देय ठहराया जाएगा, उसके भुगतान में अपने अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित Treasury Bills इस्तेमाल करने का प्रस्ताव उसने दिया है। इस तरह के किसी भी समायोजन के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरणों की मंजूरी जरूरी होगी।

वित्तीय नतीजों में चेयरमैन टॉड मोयो ने कहा कि 30 सितंबर तक के छह महीनों में समूह ने जिम्बाब्वे में US $193 million से अधिक कर चुकाया, जो एक साल पहले की इसी अवधि से 31% ज्यादा है। डेल्टा ने अपने कुल कर योगदान की ओर यह दिखाने के लिए ध्यान दिलाया है कि विवाद पुराने आकलनों के हिसाब-किताब से जुड़ा है, न कि कर दायित्वों को पूरा करने से इनकार करने से।

अब Fiscal Court के सामने जो कानूनी अंतर है, वह दोनों पक्षों के लिए अहम है। कोई आकलन कानूनन वैध हो सकता है, जबकि उसकी रकम को चुनौती दी जा सकती है—यदि करदाता गणना, पहले किए गए भुगतानों के आवंटन या कर प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल किए गए मुद्रा-आधार पर आपत्ति करता है। इसलिए अदालत का फैसला सिर्फ यह तय नहीं कर सकता कि डेल्टा पर कोई रकम बकाया है या नहीं, बल्कि यह भी कि पहले के भुगतानों का सही श्रेय देने के बाद कितनी राशि देय रह जाती है।

इसका असर अदालत से बाहर भी पड़ता है। डेल्टा जिम्बाब्वे के सबसे बड़े पेय उत्पादकों में से एक है और इतने बड़े कर मामले का असर नकदी उपलब्धता, उधार लेने की क्षमता और निवेश संबंधी फैसलों पर पड़ सकता है। बीयर उत्पादकों और पेय क्षेत्र की अन्य कंपनियों के लिए यह विवाद उन कर और विदेशी मुद्रा जोखिमों को रेखांकित करता है, जो अस्थिर मुद्रा व्यवस्थाओं में बिक्री, शुल्क और परिचालन लागत के बदलावों के साथ बढ़ सकते हैं। यदि पुराने बड़े दावे लंबे समय तक अनिश्चित बने रहें, तो कंपनियां विस्तार, पूंजीगत खर्च और कार्यशील पूंजी के प्रबंधन को लेकर अधिक

सतर्क हो सकती हैं।

इस मामले का जिम्बाब्वे के विनिर्माताओं और अन्य बड़े करदाताओं के लिए भी व्यापक महत्व है। कारोबारों को ऐसे स्पष्ट और लगातार लागू होने वाले नियमों की जरूरत है जिनसे कर देनदारियों का आकलन किया जा सके—खासकर तब, जब प्राधिकरण वर्षों पहले अलग मुद्रा नियमों के तहत किए गए भुगतानों की फिर से समीक्षा करें। इस प्रक्रिया में अनिश्चितता वित्तीय रिपोर्टिंग, दीर्घकालिक योजना और मूल्य निर्धारण संबंधी फैसलों को जटिल बना सकती है।

ZIMRA के लिए यह मामला इस बात की परीक्षा हो सकता है कि पुराने कर दायित्वों की दोबारा गणना कितनी पारदर्शी और एकसमान तरीके से की जा सकती है, जब मूल भुगतान स्थानीय मुद्रा में किए गए हों, लेकिन बाद के आकलन विदेशी मुद्रा में व्यक्त हों। डेल्टा का तात्कालिक लक्ष्य सीमित है : अदालत को यह मानने के लिए राजी करना कि उसके पहले के भुगतान कानूनी रूप से प्रभावी थे और बकाया दावे को घटाने के लिए उनका श्रेय दिया जाना चाहिए।

शनिवार, 14 नवंबर तक कार्यवाही का कोई निपटारा नहीं हुआ था। न तो अंतिम देनदारी सार्वजनिक की गई है और न ही फैसले की समय-सीमा। अदालत के निर्णय तक यह विवाद जिम्बाब्वे के कारोबारी क्षेत्र में बारीकी से देखा जाता रहेगा, खासकर पेय उत्पादकों के बीच, जो कर, मुद्रा और नकदी प्रवाह के ऐसे ही दबावों का सामना करते हैं।